प्रतिरक्षा भारती
Pratiraksha Bharti

भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ का मुख पत्र

सितम्बर २०२४ • वर्ष-विंशति (२१) • अंक ०६ • मूल्य : १० • वार्षिक मूल्य : १२०

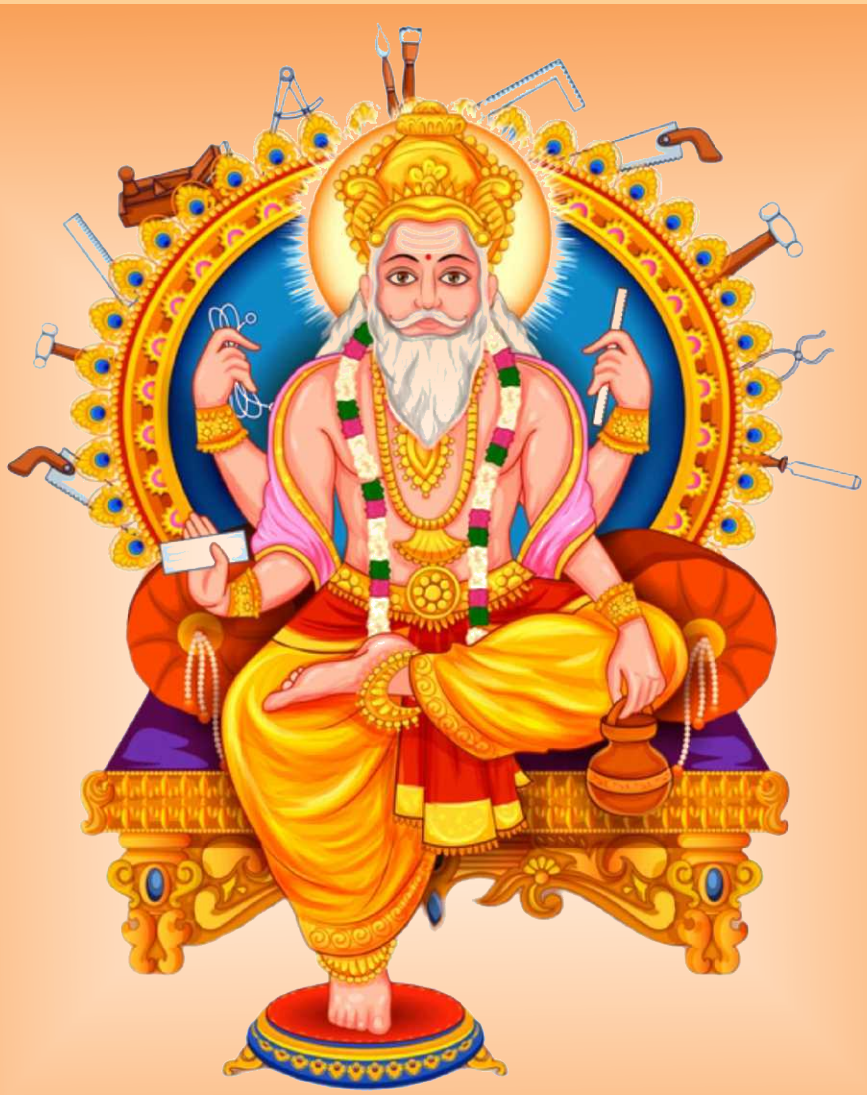

राष्ट्रीय श्रमिक दिवस

17 सितम्बर विश्वकर्मा जयंती

रक्षामंत्री भारत सरकार श्री राजनाथ सिंह जी से यूनिफाइड पेंशन स्कीम में संशोधन हेतु ज्ञापन देते हुए
भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ एवं सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ के पदाधिकारीगण

रक्षासचिव भारत सरकार श्री आर. के. सिंह (IAS) जी से रक्षा कर्मचारियों के विभिन्न मुद्दों पर ज्ञापन देते हुए
भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ एवं सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ के पदाधिकारीगण

सम्पादक की कलम से

– श्री साधू सिंह

कर्मचारी साथियों

जैसा कि आप सभी जानते है कि 1जनवरी 2004 से हमारी पुरानी पेंशन स्कीम CCS पेंशन रूल्स 1972 को समाप्त करके NPS लागू किया गया। इस कृत्य में यह जानकारी आप सभी को देना जरूरी है कि NPS का प्रारूप तत्कालीन माननीय अटल जी की सरकार के समय तय हुआ जिसका नोटिफिकेशन 22 दिसम्बर 2003 को हुआ। इस निर्णय में नेशनल कौंसिल JCM की सहमति थी। नोटिफिकेशन होने के तुरंत बाद भारतीय मजदूर संघ, सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ और भारतीय मजदूर संघ से सम्बद्ध सभी संगठनों ने जोरदार विरोध किया। माननीय अटल जी प्रधानमंत्री और भारतीय मजदूर संघ से वार्ता हुई और NPS के निर्णय को वापस लेने पर जोर दिया। लम्बी वार्ता के बाद सरकार ने आश्वासन दिया कि अभी NPS को लागू नहीं करते। चुनाव सर पर है चुनाव के बाद इस पर विचार करेंगे। अप्रैल 2004 में चुनाव सम्पन्न हुए। अटलजी की सरकार गिर गई और केंद्र में माननीय मनमोहन सिंह के नेतृत्व में UPA सरकार सत्तारूढ़ हुई। माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार ने बिना किसी संशोधन के अगस्त 2004 में एक्सिक्यूटिव आर्डर करके अटल जी की सरकार द्वारा नोटीफाइड NPS को ज्यों का त्यों लागू कर दिया गया। भारतीय मजदूर संघ ने कड़ा विरोध फिर से किया लेकिन नेशनल कॉउन्सिल की सहमति के कारण कुछ भी नहीं हो पाया। उस समय वामपंथी बिचार धारा के किसी भी संगठन ने इसका विरोध नहीं किया। चाहे AIDEF हो या रेलवे का इनका संगठन हो। 2004 से 2014 तक यह शांति पूर्वक बैठे रहे। और एक भी न संशोधन हुआ और न ops लागू हुआ। जबकि UPA 1 में वामपंथी विचारधारा सरकार में सम्मलित थी और जो चाहती थी वह सब कर लेती थी। आप सभी को याद होगा कि आतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिये पोटा कानून को पहली कैबनेट की बैठक में इन्होंने समाप्त कर दिया। विनिवेश मंत्रालय समाप्त कर दिया जो राजग सरकार ने बनाये थे। लेकिन कर्मचारियों के लिये लाई गई NPS को समाप्त नहीं कराया गया कभी भी इसके लिये इन लोगों ने आवाज ही नहीं उठाई। 2014 में UPA सरकार गई। लेकिन 10 साल तक इनकी चुप्पी के कारण NPS में कुछ भी नहीं हुआ।

मित्रों भारतीय मजदूर संघ और सम्बद्ध संगठनों ने 2004 से ही लगातार विरोध जारी रखा। कई बार आंदोलन किया अपने अधिवेशनों में प्रस्ताव पारित करके विरोध किया। सितम्बर 2013 में कांग्रेस सरकार NPS को कानूनी जामा पहनाने के लिये दोनों सदनों में बिल लेकर आई जो सर्वसम्मति से दोनों सदनों में पास हो गया इन वामपंथियों और इंटक के लोगों ने चुप्पी साध ली। भारतीय मजदूर संघ ने जब PFRDA बिल सदन में लाया गया उस दिन सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ के नेतृत्व में दिल्ली में प्रदर्शन किया। परन्तु इनके समर्थन के कारण ही PFRDABILL पास हो गया।

मित्रों 2014 में फिर से भाजपा नीत राजग सरकार सत्ता में आई भारतीय मजदूर संघ और सम्बद्ध महासंघो ने अपना आंदोलन जारी रखा। देश के वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी से हमारी वार्ता हुई और गारेण्टेड पेंशन स्कीम OPS पुनः लागू करने की मांग रखी साथ ही ग्रेच्यूटी जो 2004 में समाप्त कर दी थी उसे 2016 में पुनः लागू कराया यह कार्य हमारे आंदोलनों से ही सम्भव हुआ। मित्रो 2004 से 2016 तक आप ग्रेच्यूटी से वंचित थे यह हमारे प्रयास की पहली सफलता थी। हमने अपने प्रयासों को जारी रखा उससे फैमली पेंशन, 10 प्रतिशत से 14 प्रतिशत सरकारी कंट्रीब्यूशन हमारे आंदोलनों से ही सम्भव हुआ। यह तो 2019 में जब इनको लगा कि भारतीय मजदूर संघ लगातार कुछ न कुछ कराने में सफल हो रहा है तब यह जागे और आंदोलन की शुरुआत की। हमारा आंदोलन कोरोना काल में भी जारी रहा। हमने राज्य स्तर पर यूनिट स्तर पर आंदोलन किया 17 नबम्बर 2022 और 22 नबम्बर 2023 में दिल्ली में बड़े प्रदर्शन किया। हमारे प्रदर्शन से ही परेशान होकर सरकार ने NPS में संशोधन के लिये श्री टी. वी. सोमनाथन के नेतृत्व में कमेटी गठित की हमने अपना लिखित प्रतिवेदन दिया ज्ञापन दिया और OPS की मांग की। लेकिन कर्मचारियों का दुर्भाग्य कि इन्हें फिर से नेशनल कौंसिल में अधिपत्व के कारण वार्ता में बुला लिया और इनको गद्दारी करने का मौका मिल गया और 24 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री जी ने नेशनल कौंसिल JCM को वार्ता के लिये बुलाया। इन्होंने बड़ी ही चालाकी से भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के प्रतिनिधि को बाहर कर इंटक और लाल झंडे के लोगों को लेकर प्रधानमंत्री के पास गये और जो उन्होंने कहा उसे स्वीकार करके चले आये और मीडिया के सामने अपनी पीठ थपथपाने लगे। मिनिमम पेंशन की गारंटी महंगाई भत्ते के साथ हुई। लेकिन कर्मचारी को सेवानिवृत्त के समय क्या मिलेगा यह भी नहीं सोचा। 10 प्रतिशत प्रति 6 माह पर सहमति देकर गद्दारी की। कर्मचारी का जो 10 प्रतिशत कटेगा वह वापस नहीं होगा। जो भी फण्ड जमा होगा सब सरकार अपने पास रख रही है उस पर सहमति देकर चले आये।

AIDEF का यह कहना कि हमने तो बायकाट किया जबकि मीटिंग में बुलाया गया एक अवसर था अपनी बात रखने का लेकिन आपने मीटिंग में न जाकर उस अवसर को जानबूझकर छोड़ दिया। आप मीटिंग में जाते और वहाँ अपनी बात रखकर न सुने जाने पर बायकाट करते वह बायकाट होता न कि चालाकी दिखाते हुए अपनी मूक सहमति देना यह भी गद्दारी ही है।

मित्रों कुछ लोग यह कह रहे है कि भारतीय मजदूर संघ ने UPS को स्वीकार किया यह सरासर झूठ है। हमने यह कहा कि सरकार एक कदम आगे बढ़ी है। गारेण्टेड पेंशन महंगाई भत्ता सहित यह ठीक है लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ी दिख रही है उस पर पूरी रिपोर्ट देखने के बाद कार्यवाही करेंगे। हमने सरकार के सामने अपनी मंशा प्रकट कर दी है।

1. अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता सहित 20 वर्ष में ही मिलना चाहिये ताकि सभी कर्मचारियों को समान लाभ मिल सके।
2. फैमिली पेंशन कर्मचारी की मृत्यु के बाद 10 वर्ष तक पूरी पेंशन प्रदान की जाय और न्यूनतम पेंशन की तरह फैमिली पेंशन न्यूनतम 10 हजार रु होना चाहिये।
3. वेतन आयोग और अन्य माध्यम से पेंशन संशोधन की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिये।
4. 80 वर्ष, 85 वर्ष, 90 वर्ष, 95 वर्ष, और 100 वर्ष की उम्र होने पर 20, 25, 30, 50 और 100 प्रतिशत की वृद्धि यथावत रखी जाये।
5. अविवाहित, विधवा,तलाकशुदा पुत्री को फैमिली पेंशन का लाभ यथावत रखा जाय।
6. प्रति 6 माह में वेतन और महंगाई भत्ता का 10 प्रतिशत के स्थान पर 50 प्रतिशत लमशम amuont प्रदान किया जाय या कर्मचारी का जो 10 प्रतिशत जमा हो रहा है वह ब्याज सहित वापस सेवा निवृत्ति के समय किया जाय।
7. कोई कर्मचारी VRS लेता है तो उसे VRS की तिथि से ही पेंशन प्रदान की जाय।

मित्रों भारतीय मजदूर संघ का स्पष्ट मत है कि हमारे कर्मचारियों को OPS या OPS की तरह सभी लाभ प्रदान किया जाय और यह नहीं होने तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। ❐

'मैं' और 'हम'

संकलन–
राष्ट्र जीवन की दिशा

प्रत्येक देशभक्त व्यक्ति की ऐसी इच्छा होना स्वाभाविक ही है कि अपना देश वैभवशाली बने। राष्ट्र सुखी, सम्पन्न हो। राष्ट्रीय उत्पादन बढ़े। बेकारी, भुखमरी, बेरोजगारी, अशांति का अन्त हो। न्याय सुलभ हो। आपसी झगड़े समाप्त हों। साम्प्रदायिक, क्षेत्रीय, भाषायी संकुचितताओं से ऊपर उठकर लोगों के सोचने, विचारने का तरीका हो। दलीय अभिनिवेशों से नेतागण मुक्त हों। भारत अपने राष्ट्रीय स्वरूप में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक सभी प्रकार के क्षेत्रों में लोककल्याणकारी सिद्ध हो। जिसमें ऐसी इच्छा निर्माण नहीं होती हो उसे भारतीय तो क्या मानव कहना भी कठिन है। स्व. मैथिलीशरण जी गुप्त के शब्दों में कहना हो तो 'जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं, नरपशु निरा है और मृतक समान है।' अपने देश को गौरवशाली देखने की इच्छा प्रत्येक जीवन्त भारतीय के हृदय में उठना स्वाभाविक है।

अस्तु, राष्ट्र–वैभव प्राप्त करने का अर्थ क्या है? कुछ लोग इस सन्दर्भ में अधूरे चिन्तन की ओर बढ़ते हैं। जो राष्ट्रीय प्रगति को व्यक्तिगत लाभालाभ की दृष्टि से देखने वाले लोग हैं उनके सोचने का दायरा केवल यहीं तक सीमित है कि राष्ट्र के वैभवशाली होने का अर्थ व्यक्ति का अपना जीवन सुखी–सम्पन्न होना है। ऐसे लोग पढ़ाई–लिखाई, व्यापार, परिश्रम और रात–दिन की सारी दौड़–धूप इसी उद्देश्य से करते हैं कि 'मैं' व्यक्तिगत रीति से बड़ा से बड़ा हो जाऊँ। उनकी महत्वाकांक्षाएँ, बोलने में भले ही वे राष्ट्रीय दिखाई देती हों किन्तु वास्तविकता में वे व्यक्तिगत हैं। व्यक्तिगत आकांक्षा को लेकर किये गये कार्यों में भी कुछ न कुछ अध्यवसाय तो होता ही है इसलिए कई बार ऐसा तर्क भी दिया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति अगर प्रगति कर ले तो राष्ट्र की प्रगति हो जावेगी। किन्तु यह तर्क महज एक धोखा है। राष्ट्र की सर्वतोमुखी प्रगति अकेले अकेले व्यक्ति द्वारा नहीं हो सकती। स्वयं व्यक्ति भी अपने आप में कुछ नहीं कर सकता। यदि हम थोड़ी गहराई से विचार करें तो इसी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि 'मैं' का व्यावहारिक अर्थ है 'हम'।

मेरा नाम है दीनदयाल। इस नाम के साथ 'मैं' जुड़ा है। इसी से लोग मुझे पहिचानते हैं। मेरा प्रत्येक कार्य इसी नाम से समझा जाता है। इसके साथ मेरा मोह होना स्वाभाविक है। यदि गहरी नींद में मुझे कोई इस नाम से पुकारता है तो मैं जाग उठता हूँ। भारी भीड़ में हम जा रहे हों। बहुत कोलाहल को चीरकर कोई मेरा नाम लेकर बुलाये तो मैं सतर्क हो जाता हूँ। उस कोलाहल और भीड़ में भी मेरा 'मैं' जाग्रत रहता है। इतना गहरा सम्बन्ध मुझसे मेरे इस नाम का है। किन्तु यह नाम भी मुझे क्यों मिला ? दीनदयाल के बदले मेरा नाम 'मि. जॉन क्यों नहीं रखा गया ? या विश्व में करोड़ों अन्य नाम हैं, फिर यही नाम क्यों रखा गया ? कोई कह सकता है कि माँ ने यह नाम रख दिया। किन्तु माँ ने यही नाम क्यों रखा ? रूसी, चीनी, ईसाई, तुर्की, अरबी आदि नामों में से कोई क्यों नहीं रखा ? साफ है कि जिस समाज का मैं अंग हूँ उसके अनुरूप नामाभिधान हुआ।

अर्थ यह है कि जन्म के लिए मेरा सम्बन्ध पूज्य माता–पिता से है किन्तु जिस दिन मेरा नामकरण–संस्कार हुआ मैं समाज का अंग बन गया। मेरी बोलने की शक्ति विकसित हुई तो भाषा भी मुझे समाज से मिली। मातृभाषा प्राप्त हुई। बड़े हुए तो सभ्य बने। इसका सम्बन्ध भी समाज से है। यानी समाज ने शिक्षा देकर बड़ा किया। जितने सुख–दुख के अवसर आये सबमें समाज उपस्थित हुआ। यहां तक कि सुख–दुख की अनुभूतियां भी समाज ने दीं। घर में कोई सुखदायी कार्य हो–विवाह, पुत्रजन्म या गृह–निर्माण, तो इच्छा होती है कि चार लोग एकत्रित हों। लोग न आयें तो बचत ही होगी ऐसा सोचकर कोई सन्तोष नहीं कर लेता। बड़ी तीव्रता से चाहता है कि सब लोग सम्मिलित हों। समाज ने अच्छा कहा तो मन प्रसन्न होता है। बुरा कहा तो दुखी। इस समाज के साथ इतना गहरा सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। यहाँ तक कि कोई समाज को बुरा कहे तो असहनीय हो जाता है 'सबसे कठिन जाति अपमाना' वाली गोस्वामी तुलसीदास जी की उक्ति चरितार्थ हो जाती है। एक बार मैं रेलगाड़ी में प्रवास कर रहा था। सवारियों में आपसी तू–तू मैं–मैं हो गई। बहस ने गाली–गलौज का रूप ले लिया। उनमें एक सज्जन पंजाबी थे। उन्हें संकेत कर सभी पंजाबियों पर एक व्यक्ति ने ताना कस दिया। बस फिर क्या था। वे बोले–'देखो भाई, अब तक तुम मुझे ही उल्टा–सीधा कह रहे थे किन्तु अब तुमने सब पंजाबियों को बुरा बताया है। यह मुझे सहन नहीं हो सकता।' इतना कहकर वे प्रतिकार करने की सिद्धता में लाल हो उठे। अब सोचना चाहिए कि सब पंजाबी लोग तो वहाँ उपस्थित थे नहीं फिर भी इस व्यक्ति में वे जरूर थे। इसी प्रकार कोई भगवान रामचन्द्र, कृष्ण, बुद्ध, शिवाजी, गुरु गोविन्दसिंह, नानक, कबीर, रामदास,

मीरा, तुलसी, गांधी, पटेल आदि में से किसी को बुरा कहे तो हमारे अन्दर बैठा यह 'मैं' जाग उठता है। तब केवल मेरे शरीर तक ही सीमित विचार नहीं होता। 'मैं' समाज बनकर उपस्थित होता है। 'मैं' का सम्बन्ध यदि शरीर तक ही होता तो कोई इन महापुरुषों को कितना ही कहता तो कुछ भी नहीं बिगड़ता। किन्तु इस 'मैं' में ये महापुरुष कहीं अवश्य विराजमान हैं। विदेशों में खेलों कि प्रतियोगिताएँ होती हैं। तब भारत की टीम विजयी होने पर हम प्रसन्नता से नाच उठते हैं, मिठाई बांटते हैं, आनन्द होता है। भारतीय टीम हारने पर दुःख होता है, भारत की विजय पर 'मैं' प्रसन्न और हार में 'मैं' दुखी होता है। इस 'मैं' में सारा देश भी आता है। इस प्रकार हम अनेक प्रसंगों पर यह पाते है कि 'मैं' वास्तव मे 'हम' ही है।

'हम' ही महत्वपूर्ण है सब कुछ सामूहिक जीवन पर ही निर्भर है। वैभव भी सामूहिक जीवन की एक विशेष स्थिति का नाम है। एक सज्जन विदेशों की यात्रा कर लौटे हैं। उन्होंने लेख लिखकर बहुत दुःख प्रकट किया। मैंने पूछा इतने दुखी क्यों हैं ? तो बोले, 'क्या बताऊं, विश्व के सभी देशों में हिन्दुस्तान के संबंध में एक ही धारणा है कि यह भिखारियों का देश है।' मैंने उनसे पूछा कि 'तुमने तो भीख नहीं मांगी ?' वे बोले, 'नहीं, किन्तु यह कैसे सहा जा सकता है कि भारत भीख मांग रहा है।' याने राष्ट्रीय अपमान में हम सबका अपमान है। उसी प्रकार जब भारत–पाक युद्ध के समय भारतीय सैनिक शत्रु को पराजित कर मोर्चे पर आगे बढ़ने लगे तो जीत की खुशी में नारे लगाये गये। राष्ट्रीय सफलता पर स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करने लगे। यानि राष्ट्र के वैभव में हमारा वैभव निगड़ित है।

वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति का जीवन नाशवान है फिर भी भगत सिंह को सब याद करते हैं। हकीकत राय, गुरु तेग बहादुर को याद करते हैं। एक लम्बी परम्परा है जिनका स्मरण होता है। इन सब बलिदानी महापुरुषों ने अपने शरीर की परवाह नहीं की। यह 'हम' ही था जिसने 'मैं' को इतना ऊंचा उठने की प्रेरणा दी। हंसते–हंसते बलिदान हो गये। कहा कि शरीर नश्वर है। समाज अमर है। समाज को जीवित रखने के लिये व्यक्ति ने बलिदान दिये। समाज ने उन्हें अपनी स्मृतियों में संजोकर अमर बना दिया। दोनों अमर हुए। इन बलिदानों को क्या आत्महत्या कहा जावेगा ? नही। बलिदान और आत्महत्या में अन्तर है। आत्महत्या 'मैं' तक सीमित भावना है, इसलिए गलत है। किन्तु यही कार्य जब हम के लिए होता है तो बलिदान कहा जाता है। शरीर जब देश के लिए, समाज के लिए अर्पित हो तो गौरव की बात है। उसमें चिन्ता किस प्रकार की ? वह वरेण्य है। इससे समाज को शक्ति मिलती है। बलिदान से श्रेष्ठ कार्य के पौधे सींचे जाते है। 'मैं' का वास्तविक अर्थ 'हम' गुंजित होता है। जहां 'हम' याने सामूहिक उत्तरदायित्व उभरा कि शक्ति का प्रस्फुटन होता है। इसलिए बलिदान राष्ट्र को नव चौतन्य प्रदान करने वाले सिद्ध होते हैं।

'हम' ही वह मूलभूत तथ्य है जो 'मैं' को सार्थक बनाता है। आर्थिक, नैतिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार के विकास इसी तथ्य में निहित हैं। कोई व्यक्ति यदि हिमालय की किसी कंदरा में जाकर योगाभ्यास करे और 'मैं' से चलकर 'हम' तक न पहुँचेः केवल व्यक्तिगत मोक्ष की आकांक्षा से ही सब कुछ करे, योगाभ्यास करें तो भी उसे मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति इतनी छोटी चीज नही है जो समाज को छोड़ कर किसी एक को एकान्त में मिल जाय। किसी प्रकार की सिद्धि भले ही प्राप्त हो जाय तथापि वह सिद्धि तब तक बेकार ही है जब तक वह अपने चारों ओर फैले समाज बन्धुओं को उन्नत करने में समायोजित न हो। कुछ लोगों की ऐसी गलत धारणा है कि समाज अधःपतित रहते हुए भी केवल वही अकेले मुक्ति के अधिकारी बन सकते हैं। यह गलत है। मुक्ति नाम की व्यक्तिगत कोई चीज नहीं है। मुक्ति भी समष्टिगत है। जब समाज मुक्त होगा, तो ऊँचा उठेगा। उन्नत होगा तभी व्यक्ति को शांति मिल सकती है। इसलिए संन्यास आश्रम में प्रवेश करने वाले भी लोकसंग्रह का दायित्व ग्रहण करते हैं। लोकमान्य तिलक के गीता–रहस्य में वर्णित कर्मयोग का भी यही निष्कर्ष है। शास्त्रों में वर्णित एक श्लोक उद्धृत कर उन्होंने कहा कि अपना धर्म–कर्म छोड़कर जो कृष्ण–कृष्ण चिल्लाते हैं वे पापी है। कृष्ण स्वयं धर्म की स्थापना के लिए यत्नशील रहे। 'धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे' की घोषणा हुई। भगवान इसी के लिए अवतरित होते हैं। ऐसा वर्णन हमें सुनने को नहीं मिलता कि भगवान का अवतार हुआ तो वे कहीं किसी गुफा में बैठकर एकान्त मुक्ति की साधना में लग गये। भगवान राम का चरित्र हमारे सामने है। उखड़ी हुई मर्यादाओं और च्युत लक्ष्यों को पुनः स्थापित कर धर्म की विजय उनके आश्रय से प्राप्त हुई। इसलिए समाज को उन्नत बनाने का काम भगवान का काम है। अपने निज के लिए किया गया काम शैतान का काम है। राष्ट्रभक्ति, समाजभक्ति ही भगवान–भक्ति है।

'मैं' और 'हम' में यही अन्तर है। महाभारत का उदाहरण लें। महाभारत में कहा गया है कि 'यतो धर्मस्ततोजयः याने जहाँ धर्म है, वहीं विजय है। तब लोग एक प्रश्न करते हैं कि महाभारत के युद्ध में कौरवों के जितने प्रमुख सेनापति थे वे चालाकी से मारे गये। भीष्म को मारने के लिए शिखण्डी को खड़ा किया गया। द्रोणाचार्य

को युद्ध समाप्त करने के लिए युधिष्ठिर ने झूठ बोला। कर्ण तब मारा गया जब वह अपने रथ का पहिया उठाने का अर्जुन से अवसर मांग रहा था। जयद्रथ की मृत्यु का कारण सूर्य का बादलों में छिपना और प्रकट होना बताया जाता है। दुर्योधन की मृत्यु तो कमर के नीचे गदा मारने से ही भीम के हाथों हुई। इसके आधार पर पूछा जा सकता है कि पाण्डवों की जीत के लिए ये सब जो कार्य हुए क्या उन्हें धर्मानुकूल कहा जावेगा ? पाण्डवों ने छल किया। फिर भी 'जहाँ धर्म वहाँ जय' की घोषणा वेदव्यास करते हैं तो क्या यह परस्पर विरोधी बात नहीं है? क्या धर्म के नाम पर अधर्म नहीं हुआ? इसका उत्तर खोजने पर हमें विदित होगा कि कौरव और पाण्डव के पक्ष के बीच एक बड़ा मूलगामी अन्तर था। कौरव–पक्ष का प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिवादी था। इसलिए अनर्थ का साथ दे रहा था। भीष्म पितामह महान थे किन्तु उनका व्यक्तिवादी दृष्टिकोण इसी बात से प्रकट हो जाता है किं उन्होंने सोचा– 'मैंने प्रतिज्ञा की है, शिखण्डी के आने के बाद मैं बाण नहीं चलाऊँगा। भीष्म पितामह ने यह नहीं सोचा कि वे सेनापति हैं, उन पर सेना का भार है। उन्हें केवल अपनी निजी प्रतिज्ञा की चिन्ता थी। दूसरी ओर अर्जुन ने जब इसी प्रकार का अपना व्यक्तिवादी दृष्टिकोण बताकर शस्त्र रखने की बात कही तो भगवान श्रीकृष्ण ने उन्हें धर्म का रहस्य बताया कि तू यदि अपने तक सोचता है तो व्यर्थ सोचता है। अर्जुन ने 'मैं' को छोड़ा और 'हम' को स्वीकार किया। भीष्म पितामह ने न अपने पक्ष का, न समाज का किसी का भी विचार नहीं किया। केवल 'मैं' का विचार मात्र किया। इधर भगवान कृष्ण ने भी महाभारत में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की थी। फिर भी जब अवसर ऐसा ही आ गया कि उन्हें शस्त्र ग्रहण करने पड़े तो उन्होंने आगा–पीछा नहीं किया। समष्टि के हित के लिए उन्होंने यह नहीं सोचा कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से क्या कहा जायगा? धर्मराज युधिष्ठिर ने भी उनका कहना माना और समष्टि की मांग के समक्ष उन्होंने अपना रथ थोड़ा नीचा कर लिया। इधर द्रोणाचार्य को पुत्र का मोह था। वे पुत्र–वध का समाचार पाकर शस्त्र छोड़ बैठे। कर्ण ने तो सूर्य द्वारा प्रदत्त अपने कवच–कुण्डल ही इन्द्र को दे दिए। यद्यपि सूर्य ने चेतावनी दी थी कि कवच–कुण्डल न देना। किन्तु कर्ण को अपनी दानवीरता का ध्यान था। उसने सबका विचार नहीं किया। इधर कुन्ती ने आवश्यकता पड़ने पर जाकर कर्ण को बता दिया कि वह उसका ही पुत्र है। कुन्ती जब कुंवारी थी तब कर्ण का जन्म हुआ था। यह बात बताने में कुन्ती को निजी अपमान सहना पड़ा। किन्तु समष्टि के लिए उसने न केवल यह सत्य घोषित किया वरन् अर्जुन को छोड़कर अन्य किसी पाण्डव पर कर्ण बाण नहीं चलायेगा यह वचन भी कुन्ती ने प्राप्त कर लिया। इधर भीष्म की मृत्यु का रहस्य किसी को पता नहीं था। किन्तु द्रोपदी ने जाकर जब पूछा तो भीष्म ने बता दिया कि शिखण्डी के सामने आने पर वे युद्ध करना बन्द कर देंगे। भीष्म ने यह नहीं सोचा कि सेनापति का ऐसा करना सबके हित में नहीं है। किन्तु उन्हें सबका नहीं अपना ही ख्याल रहा। इसलिए हम पाते हैं कि कौरव–पक्ष में पाण्डवों के पक्ष की तुलना में एक से एक बढ़–चढ़ कर योद्धा और शूर थे फिर भी उनकी सबकी कृतियाँ अलग–अलग थीं, सबका मिलकर कोई एक कार्य संचालन नहीं था। सबको अपनी–अपनी ही चिन्ता थी। भीष्म को प्रतिज्ञा की चिन्ता थी, द्रोणाचार्य को पुत्र का मोह था, दुर्योधन को मात्र अपने, राज्य की चिन्ता थी। उधर पाण्डवों के पक्ष में सबका मिलकर कार्य था। उनमें से प्रत्येक ने अपने–अपने व्यक्तिवादी दृष्टिकोण को छोड़ा। भगवान कृष्ण के नेतृत्व मैं एकजुट होकर जो भी कार्य आया निभाया। कर्ण से भीख मांगना था– मांगी, झूठ बोलने का क्षण आया– बोला, निजी गुप्त रहस्य का उद्घाटन कर स्वयं लांछित होने का प्रश्न आया तो भी चिन्ता नहीं की, जैसा कृष्ण ने कहा सब करते रहे। अपना–अपना आग्रह छोड़कर समष्टि के लिए ही कार्यरत हुए। उनका समष्टि का विचार कर कार्य करने का ढंग ही धर्म हुआ और व्यक्तिवादी आधार पर सोचने के कारण कौरवों का पक्ष अधर्म का पक्ष गिना गया। जीत धर्म की हुई अधर्म की नहीं। याने समष्टिवाद ही धर्म है। व्यक्तिवाद अधर्म है। राष्ट्र के लिए काम करना धर्म है। राष्ट्र–कार्य को साधने के लिए जो कुछ आ पड़े करना ही उचित है। सच, झूठ, सबकी कसौटी समष्टि का हित है। इसका अर्थ यह नहीं कि धर्मराज ने झूठ बोला इसलिए हम भी अपने दैनिक जीवन में झूठ बोलने लगें। झूठ बोलना तो खराबः ही गिना जावेगा। प्रश्न है कि राष्ट्र का, समष्टि का विचार कर कार्य किया गया है या नहीं? जैसे किसी की हत्या करना पाप है किन्तु युद्ध में लड़ने वाले सैनिक को कोई हत्यारा नहीं कहता। शत्रु पर वार करना यह सैनिक का धर्म है। युद्ध में सैनिक रोज हिंसा करता है। उसे परमवीर चक्र देकर हम सम्मानित करते हैं। क्योंकि इस कार्य में वह व्यक्तिवादी ढंग से नहीं सोच रहा। राष्ट्र का विचार कर उसने आचरण किया है। इसलिए अभिनन्दनीय है। यही आचरण यदि व्यक्ति जीवन में कोई करे तो उसे फांसी की सजा होगी। किन्तु युद्ध में शत्रु का विनाश करना राष्ट्र–रक्षा का पुनीत कर्तव्य बन जाता है। शत्रु–पक्ष में जाकर जासूसी करते समय कितने ही कार्य करने पड़ते हैं, जिन्हें व्यक्ति–जीवन में अनुचित ही कहा जावेगा। झूठ बोलना, चोरी करना और कितने ही प्रकार के कर्म करके शत्रु पक्ष के भेद लाने होते हैं। किन्तु चूँकि ये कार्य समष्टि के हित का ध्यान रखकर सम्पन्न किये जाते 'हैं इसलिए वे सम्मानित होते हैं।

राष्ट्र के लिए की गई चोरी, चोरी नहीं रहतीय याने कर्म का महत्व इस बात पर है कि किस विचार से किया गया ? यदि समष्टि का विचार कर किया गया तो पुण्यकर्म ही है। समष्टि का विचार कर कार्य करने वाले लोगों की शक्ति ही सामूहिक संगठित शक्ति है। व्यक्तिवादी संगठित शक्ति नहीं बना पाते। इसीलिए कहा गया है कि राष्ट्रीयता का भाव ही शक्ति का मार्ग है।

यह सामूहिक भाव याने राष्ट्रीयता ही वह कसौटी है जिस पर हमारी प्रत्येक कृति, प्रत्येक व्यवस्था ठीक या गलत गिनी जावेगी। उदाहरणार्थ, प्रजातंत्र में प्राप्त नागरिकों के अधिकारों को ही लें। वोट का अधिकार है, वोट देते समय यदि राष्ट्र का विचार रहा तो धर्म होगा और यदि व्यक्तिगत विचार से प्रेरित होकर सम्पन्न हुआ तो अधर्म हो जावेगा। राष्ट्रीयता यदि ठीक है तो सब व्यवस्था ठीक गिनी जावेगी और यदि राष्ट्रीयता के विपरीत कार्य हुआ तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ व्यवस्था भी गलत सिद्ध होगी। जो लोग राष्ट्रीयता का मखौल उड़ाकर, राष्ट्र के विचारों को तिलांजलि देकर विभिन्न प्रकार के 'वादों' के नारों में उलझते हैं वास्तव में वे भूल करते हैं। उनके हाथ से कोई अच्छा कार्य नहीं हो सकता। समाजवाद, पूँजीवाद, प्रजातंत्र अथवा अन्य कोई भी वाद अधिक से अधिक एक रास्ता है, प्रगति का आधार नहीं। व्यक्तिगत, दलगत या वादगत कोई विचार लेकर चलने से प्रगति नहीं हो सकती। राजनीति आखिर राष्ट्र के लिए ही है। यदि राष्ट्र का विचार छोड़ दिया, याने राष्ट्र की अस्मिता, उसके इतिहास, संस्कृति, सभ्यता को छोड़ दिया तो राजनीति का क्या उपयोग ? राष्ट्र का स्मरण कर कार्य होगा तो सबका मूल्य बढ़ेगा। राष्ट्र को छोड़ा तो सब शून्य जैसा ही है। राष्ट्र का विचार लेकर आगे बढ़ें तो एक और एक मिलकर दो नहीं ग्यारह होते हैं। इस आधार पर संगठन करते जावें तो एक, एक, एक, होकर एक हजार एक सौ ग्यारह हो जाते हैं। राष्ट्रीयता छोड़ी तो दशमलव लग गया। अब चाहे जितने एक जोड़ते जायं मूल्य घटता ही जावेगा। राष्ट्र के आधार पर ही व्यक्ति की कीमत बढ़ती है। राष्ट्र को छोड़ा तो कीमत घटती है।

सामूहिक जीवन के इन संस्कारों को मजबूत करना ही प्रगति का मार्ग है। प्रत्येक व्यक्ति 'मैं' और 'मेरा' विचार त्यागकर 'हम' और 'हमारा' विचार करे। अन्यथा कई बार देखा जाता है कि व्यक्ति कहता है कि राष्ट्र के लिए जान हाजिर है और जीवन में सब कार्य व्यक्ति का विचार कर ही करता रहता है। इसमें न व्यक्ति का भला है और न ही समष्टि का। वास्तव में समष्टि के लिए कार्य करना याने धर्माचरण करने की भी शिक्षा होती है। उसमें भी संस्कार डालने होते हैं। इन संस्कारों को प्रदान करना ही राष्ट्र का संगठन करना है।

किन्तु इसका यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि 'मैं' नाम की कोई सत्ता ही नहीं है। तात्पर्य इतना ही है कि 'मैं' की सार्थकता 'हम' में होती है। व्यक्तिभाव जिसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व ढलता है आवश्यक ही होता है। व्यायाम से शरीर बलशाली होता है। संध्या उपासना करने से अन्तःकरण को शांति मिलती है. दीर्घायु प्राप्त होती है। व्यक्तिभाव से व्यक्तिशः सेवा–सुश्रुषा करने से ही यह सब हो पाता है। व्यक्ति को नीरोग, दीर्घजीवी, हृष्ट–पुष्ट, आनन्दित, प्रसन्न, कार्यक्षम, यशस्वी होना जरूरी है। जहाँ व्यक्ति निर्बल होकर निकम्मा हो जाता है वहाँ समष्टि की आराधना का पूरा लोप होना स्वाभाविक ही है। इसलिए व्यक्ति के गुण विकसित होना चाहिए। व्यक्ति निकम्मे हों तो समाज की सेवा किस प्रकार करेंगे। इसीलिए हमारे यहाँ यह भी कहा गया है कि–

अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽसंभूतिमुपासते
ततो भूय इव ते तमो य उ संभूत्यां रताः।

जो व्यक्तिवाद का अवलम्बन करते हैं वे अधःपतन को प्राप्त होते हैं परन्तु जो समष्टिवाद में रमते हैं वे उससे भी अधिक नीचे गिरते हैं।

अस्तु भारतीय तत्वज्ञानियों ने 'मैं' और 'हम' को समन्वित करने का विचार रखा है। उनका कहना है कि–

संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदोभयं सह
विनाशेन मृत्युं तीर्ध्वा संभूत्याऽमृतमश्नुते।

समष्टिवाद और व्यक्तिवाद ये दोनों साथ–साथ रहें तो लाभदायक होते हैं। व्यक्तिवाद के अनुष्ठान से व्यक्ति के कष्ट दूर किये जाते हैं और समष्टिवाद से अमरत्व की प्राप्ति होती है।

यही 'संभूय समुत्थान' का अर्थ है। संघ बनाकर उठना ही प्रगति का रास्ता है। संघ बनाकर न रहना अर्थात् व्यक्तिशः रहना, व्यक्ति का पृथक पृथक रहना असंघटित अवस्था है। इसी का नाम विनाश है क्योंकि व्यक्ति विनाश को प्राप्त होता है और संघ अजरअमर रह सकता है। मानवों का अमरत्व संघभाव से है और व्यक्ति बिखरा हुआ रहे तो व्यक्ति का नाश निश्चित है। इसलिए व्यक्तियों को गुणवान, शक्तिवान बनना चाहिए और व्यक्तिवाद छोड़कर संघशक्ति की आराधना करना चाहिए। मनुष्य अमरत्व चाहता है। वह अमरत्व संभूति से ही मिल सकता है। 'संमूत्या अमृतं अश्नुते' संघ से अमरत्व प्राप्त होता है। संघ जीवन, सामुदायिक जीवन जीना ही अमरत्व को प्राप्त करना है। इस दृष्टि से 'मैं' के वास्तविक रूप 'हम' को ग्रहण करना चाहिए। ❐

Serious Concerns Regarding the Unified Pension Scheme (UPS) and Request for Immediate Intervention.

Major Concerns Regarding the Unified Pension Scheme (UPS)

1. Inadequate Pension Structure Compared to OPS

Under the Old Pension Scheme, employees were entitled to 50% of their basic pay or the average emoluments of the last 10 months (whichever was more beneficial), after completing a qualifying service of 10 years. The UPS, however, stipulates that employees must complete 25 years of service to receive 50% of the average basic pay of the last 12 months.

This drastic increase in the qualifying service requirement is highly concerning. Many employees, particularly those recruited later in life due to age relaxations or other factors, will not be able to complete 25 years of service and will, therefore, be denied the full pension benefits they would have received under the OPS. This discrepancy makes the UPS highly disadvantageous, and we urge the government to reduce the qualifying service requirement to 10 years, in line with the OPS.

2. Silent on Pension Revision Due to Pay Upgradation

One of the most glaring omissions in the UPS is the absence of any provision for pension revision following pay upgrades or revisions as a result of subsequent Central Pay Commission recommendations. Under the OPS, pensioners benefited from revisions whenever pay scales were upgraded, ensuring that their pensions remained in alignment with current pay structures.

The UPS does not address this critical issue, leaving future pensioners vulnerable to a stagnant pension amount that does not reflect inflation or economic changes. This lack of periodic pension revision will create immense financial insecurity for retirees, especially given the rising cost of living.

3. Inadequate Family Pension Provisions

While the government has announced that family pension under the UPS will be 60% of the employee's pension, it has failed to address key issues related to family pension that were covered under the OPS. For instance, the OPS pr vided for a minimum family pension amount and special provisions in case of the death of an employee in service.

Under the OPS, family pension was determined at 30% of pay with a minimum floor of ₹9,000 per month. Additionally, if an employee died in service, the family was entitled to 50% of the employee's pay for the first 10 years following their death. These crucial protections for families are missing from the UPS, leaving employees uncertain about the security of their families in case of their premature death.

4. Unfair Lump-Sum Payment Structure

Under the NPS, employees received 60% of their pension corpus as a lump-sum payment upon retirement. However, under the UPS, the lump-sum payment has been drastically reduced. Employees will only receive a payment equivalent to 1/10th of their monthly emoluments (Basic Pay + DA) for every six months of completed service.

This structure is grossly unfair to employees who have contributed to their pension fund for decades. An employee who contributes 10% of their Basic Pay + DA for 30 years (i.e. 12x30 = 360 months) would have accumulated contributions worth 36 months of pay, yet the UPS only provides a lump-sum amount equivalent to 6 months of pay. This results in a significant financial loss (36-6 = 30 months) for the employee, further diminishing the appeal of the UPS compared to the NPS.

5. Delayed Pension for Voluntary Retirees

The UPS provisions state that employees opting for voluntary retirement before the age of 60 will not receive their pension benefits until they reach the age of 60. This arbitrary delay in pension disbursement is unjust and has caused significant unrest among employees.

We request that this provision be abolished and that employees who take voluntary retirement receive their pension from the date of their retirement, as is currently the case under the OPS.

❐

DISCUSS IMPORTANT AGENDA POINTS WITH DEFENCE SECRETARY

1. Conduction of Departmental Council Meetings/ Steering Committee Meetings regularly-

As per the JCM Scheme "the meetings of the Departmental Council should be held as often as necessary, and not less than once in four months." Prior to Main meeting, a Steering Committee meeting is held to scrutinize the agenda points for the Main meeting. Departmental Council meetings are held under Chairmanship of the Defence Secretary and this council is almost defunct/dead at this time due to non-conduction of its meeting. This is leading to pile-up of employees' grievances. Therefore, it is requested to look into this matter on urgent basis.

2. Granting of compassionate appointments to the wards of employees of Ordnance Factories & DGEME who died in harness or medically boarded out:-

It is very painful to note that none of the dependents of employees of DGEME and Ordnance Factories, hospitals & schools has been given compassionate appointment in last 02 years. Even cases of such wards are pending who have been selected for compassionate appointment and their Police Verification Reports (PVR) are submitted to concerned factories/establishments.

3. Notional extension of Court judgments to similarly placed non-petitioners in MOD:-

It is observed that the employees are being compelled to file litigations to get the similar benefits which are already granted by the Courts/Tribunals to similarly placed other employees of same Establishment/HQrs/Department. For example;

(1) Payment of Dress Allowance to industrial employees of MES, DGOS, Ordnance Factories, etc. (2) Payment of Overtime Allowance (including arrears w.e.f. 01.01.2006) in Ordnance Factories including HRA, Transport Allowance & Small Family Allowance.

4. Payment of Night Duty Allowance to Defence Civilians at par with Railways' employees:-

NDA is being granted to all eligible non-gazetted employees of Ministry of Railways upto Pay Level — 7 (including those who are granted the benefit of MACP in Pay Level – 8). However, maximum Basic Pay for working out hourly rate of NDA shall remain Rs. 43600/- i.e. the prescribed ceiling fixed vide Board's letter of even number dt. 29.09.2020. But the defence civilians are eligible for NDA, if their basic pay exceeds Rs. 43600/-, though they have to perform night duty. This discrimination should be stopped forthwith.

5. Promotion to the post of MCM & Chargeman in DGEME & DGOS: -

No vacant post of Master Craftsman & Chargeman in EME Workshops & DGOS is being filled up by promotion w.e.f. 14.06.2010 on the plea that Recruitment Rules have not been framed/ revised. These 14 years should be sufficient time for DGEME/DGOS/MOD/GoI to frame/revise a Recruitment Rule.

6. Filling of vacant posts of defence civilians through Direct Recruitment:

As per the DoPT F.No. 43014/03/2019-Estt(B), dated 21.01.2020, all Ministries / Departments have been requested to fill existing vacancies in a time-bound manner. I am writing to express our deep concern regarding the decision by the Ministry of Defence, to refrain from filling the vacancies for defence civilians in the Indian Army/Air Force/Navy, as ordered vide MoD ID No. 17(03)/2022/D(Civ-II), dated 15th July 2022. Earlier, due to the recommendations put forth by the Shekatkar Committee, already 32,000 posts of defence civilians in the Indian Army has been abolished.

7. Leave Encashment for re-employed Ex-Servicemen (PBORs):

It is requested that re-employed ex-servicemen, be granted leave encashment up to 300 days, excluding the number of days that were encashed at the time of their retirement from the Army/Air Force/Navy.

8. Payment of PLB to DGEME's employees:

The Productivity Linked Bonus has been a longstanding tradition and a source of motivation for the employees who work tirelessly to contribute to the overall objectives and success of the organization. The timely disbursement of PLB not only recognizes their hard work and dedication but also enhances their morale and festive spirit. In light of the above, we kindly request your intervention and prompt action to ensure that the employees of DGEME receive their Productivity Linked Bonus, not less than Adhoc Bonus.

9. Coast Guard related issues:

(a) Implementation of MoD instruction on the restructuring of Cadre of Technical Tradesman in Defence Establishments in modification of 6th CPC introduced vide MOD letter No. 11(5)/2009/D (Civ-I), dated 14.06.2010 in respect of Coast Guard employees;

(b) Formation of Social Dialogue Mechanism like JCM, Works Committee, Welfare Committee etc. in Coast Guard establishments; (c) Membership verification for recognition of trade unions in Base Maintenance Unit, Chennai.

10. Conversion from NPS to OPS:

The Department of Defence Production & Supplies, Ministry of Defence, vide File No. 1640/D(QA)/2002, Dated 20.05.2003, released a significant number of Group 'B,' 'C,' and 'D' posts to the Ordnance Factory Board (OFB) for direct recruitment for the years 2000-01, 2001-02, 2002-03, and 2003-04, totaling 7354 vacancies. Subsequently, the OFB granted approval for the filling up of various Non-Gazetted Officers (NGOs), Non- Industrial Employees (NIEs), and Industrial Employees (IEs) posts. All these employees should be brought under the coverage of CCS (Pension) Rules, 1972 (OPS) from NPS. ❐

National Labour Day

Shivendra Sagar Sharma

National Labour Day, celebrated on *17 September, coincides with **Vishwakarma Jayanti, a day dedicated to **Lord Vishwakarma*, the divine architect and craftsman in Hindu mythology. Vishwakarma is regarded as the creator of all tools, machines, and buildings, symbolizing the spirit of craftsmanship, engineering, and labor.

On this day, people, especially those in professions like engineering, architecture, carpentry, and manufacturing, worship Lord Vishwakarma to seek blessings for prosperity and success in their work. Factories, workshops, and workplaces are often adorned with decorations, and special prayers are held to honor the skills and labor of workers.

In India, this day highlights the dignity of labor and the contributions of the working class. It serves as a reminder to respect the craftsmanship and hard work that form the backbone of industry and development.

*Vishwakarma Jayanti, also known as **National Labour Day* on 17 September, holds deep significance in India, especially for those engaged in industries related to engineering, construction, craftsmanship, and mechanical work. The day is dedicated to *Lord Vishwakarma, who is revered as the divine architect and engineer of the gods. According to Hindu mythology, Lord Vishwakarma constructed the palaces, weapons, and tools of the gods, and he is credited with creating some of the most famous mythological cities, such as **Dwarka, **Hastinapur*, and the flying chariots of the gods.

Celebrations on Vishwakarma Jayanti:

1. **Worship and Offerings :** On this day, artisans, craftsmen, mechanics, and engineers clean and worship their tools, machines, and instruments, believing that this will bring prosperity, success, and protection from accidents. Workplaces like factories, industries, and offices arrange special pujas (prayers) to seek blessings from Lord Vishwakarma.
2. **Rituals:** Prayers are often followed by distribution of sweets, the chanting of mantras, and invoking the presence of Lord Vishwakarma to bless the tools and workspaces. People also abstain from using their tools for work on this day, considering it a mark of respect.
3. **Role in Industrial Sectors :** Vishwakarma Jayanti is particularly significant in the industrial and manufacturing sectors. Workers in fields like carpentry, mechanics, construction, metalworking, and machinery come together to celebrate this day. In factories, workshops, and other workplaces, machinery and tools are honored, signifying the importance of labor in building a nation.
4. **Unity and Respect for Labor :** In modern times, Vishwakarma Jayanti also serves as a day to recognize and honor the contributions of the labor force. By celebrating **National Labour Day* on this occasion, the significance of hard work, skill development, and respect for all kinds of labor is emphasized.
5. **Significance Beyond Hinduism :** While Vishwakarma Jayanti has deep roots in Hindu culture, its celebration has transcended religious boundaries, with people from various backgrounds, particularly those in the technical and industrial professions, observing the day with reverence for craftsmanship and labor.

The day not only serves as a religious and cultural event but also promotes a sense of pride in work and craftsmanship. It underscores the importance of skill and dedication in both traditional and modern professions, connecting the heritage of craftsmanship with contemporary industries.

❐

Government ORDERS

सत्यमेव जयते

No.1 (5)/2023/EGoM/Deemed Deput./OF/DP (M&P) Government of India Ministry of Defence Department of Defence Production Management a Policy Division, New Delhi the 9th September, 2024

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Extension of deemed deputation period of employees of erstwhile Ordnance Factory Board (OFB) in 7 new Defence Public Sector Undertakings including transfer of employees (Group A, B a C) at Directorate of Ordnance (Coordination a Services) under DDP.

The undersigned is directed to refer to OM No. 1(5)/2021/OF/DP(Plg-V)/02 dated 24" September, 2021 of this Department issued pursuant to the decision of the Cabinet dated 16.06.2021 to convert the production units of OFB into 7 Defence Public Sector Undertakings (DPSUs). Accordingly, the employees of erstwhile OFB (Group A, B & C) belonging to the 41 production units and also the identified non-production units were transferred en masse to the new DPSUs on terms of foreign service without any deputation allowance (deemed deputation) and the employees of erstwhile OFB at OFB HQ (at Kolkata), OFB New Delhi Office, OF Schools and OF Hospitals were transferred en masse to the Directorate under DDP, initially for a period of two years from the Appointed Date i.e. 01.10.2021, which was further extended by another 1 (One) year w.e.f. 1 October 2023, on same terms and conditions as issued earlier vide above DDP OM dated 24.09.2021. **The extended period is expiring on 30" September 2024.**

2. The undersigned is further directed to intimate that the Empowered Group of Ministers (EGoM) has approved the following :

2.1 To extend the period of deemed deputation of all the employees of erstwhile OFB (Group A, B & C) to 7 new DPSUs including transfer of all employees (Group A, B & C) at Directorate of Ordnance (Coordination & Services) under DDP upto 31 December, 2025 w.e.f. 015t October 2024, on same terms 1(5)/2021/OF/DP(Plg-V)/02 dated 24.09.2021.

2.2 The process of framing of all rules and regulations, consultation with stakeholders & seeking option for permanent absorption by 7 new DPSUs is required to be completed within this extended time frame. ❐

F.No55/13/2023 .-P&PW(C)(Part1) Government of India Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions Department of Pension and Pensioners' Welfare, New Delhi the 11th September, 2024

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Submission of nomination for Arrears of Pension and Commutation of Pension after introduction of Single Pension Application Form 'Form 6-A' for Central Government civil employees.

The undersigned is directed to refer to the Department of Pension and Pensioners' Welfare notification dated 16.07.2024 whereby Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 were amended and a new Single Pension Application For JTI 'Form 6-A' was introduced for submission by retiring Central Government civil employees for sanction of pension under these rules. This Application 'Form 6-A' has replaced the existing 'Form 6' and also prescribed submission of nomination, family details, undertaking to banks and other details in the single form.

2. The Department of Pension and Pensioners' Welfare vide notification dated 28.03.2014 had introduced a Common Nomination Form 'Form- A' for submission of nomination for Arrears of Pension and Commutation of Pension by the Central Government civil employees.

3. The new Single Pension Application Form 'Form 6-A', to be filled by retiring Central Government employees includes details of nomination for the Arrears of Pension and Commutation of Pension. Therefore, retiring Central Government employees are required to submit the nomination for these benefits in Form 6-A from the date of its effect as per notification dated 16.07.2024. The Common Nomination Form 'Form A' shall not be required to be submitted along with the Form 6-A.

4. However, the Central Government pensioners/ family pensioners shall continue to submit nomination for Arrears of Pension/Family Pension and Commutation of Pension in Common Nomination Form 'Form A' in the cases where the nomination is submitted separately after the retirement or for any subsequent change in the nomination made earlier by the Central Government pensioner/family pensioner.

5. All Ministries / Departments are requested to bring the contents of these orders to the notice of Controller of

Accounts/Pay and Accounts Officers and Attached Offices under them.

6. Formal amendments to the CCS (Commutation of Pension) Rules, 1981 and the Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983 in terms of the decisions contained in this order will be issued in due course.

Encl.

1. Copy of Notification No. GSA 410 (E) dated 16.07.2024
2. Copy of Notification No. GSA 235 (E) dated 28.03.2014 ❐

F. No. Z15025/44/2023/DIR/CGHS/EHS (Comp No. 8253711) I/3705508/2024 Government of India Ministry of Health & Family Welfare Department of Health & Family Welfare, New Delhi the 9th September, 2024

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Revision of Rates for Permission/ Reimbursement of Cost of Neuro implants under CGHS

In supersession of the Office Memorandum dated 04.12.2008, 8.12.2014 and 09.07.2018 regarding the permission/approval for reimbursement of the cost of Neuro implants, including Deep Brain Stimulation (DBS) Implants, Intra-thecal Pump, and Spinal Cord Stimulators for CGHS beneficiaries and those covered under CS(MA) Rules, 1944, it has now been decided to revise the rates of Neuro implants. The terms and conditions for permission/ reimbursement are:

2. Prescribing Authority:

1	OBS Implant	Neurologist of a Government Hospital
2	Intra - Thecal Pump	Any two Government Soecialists of concerned Speciality / Head of Dept. of Neurology / Neuro - Surgery.
3	Spinal Cord Stimulator	

3. Approving Authority

a. **CGHS -** Director CGHS

b. **CS(MA) Rules, 1944 -** DDG(M) or equivalent level Officer of Directorate General of Health Services

4. Approval Process:

The permission for approval for DBS and other Neuro Implants shall be accorded only after the request has been approved and recommended by the respective Standing Technical Committee as given under:

1	Addl. DG CGHS (in case of CGHS Beneficiaries) OR DDG(M)/(P), Dte. GHS (in case of CS(MA) Rules, 1944 beneficiaries)	Chairperson
2	HoD Neurology/Neuro-Surgery AIIMS, Delhi	Member
3	HoD Neurology/Neuro-Surgery R&R Hospital	Member
4	HoD Neurology/Neuro-Surgery Safadarjung Hospital	Member
5	HoD Neurology/Neuro-Surgery ABVIMS & Dr. RML	Member
6	HoD Neurology/Neuro-Surgery G. B. Pant Hospital	Member
7	AD (R&H) CGHS Delhi (in case of CGHS Beneficiaries) or Addl. DDG (MG-II) (in case of CS(MA) Rules, 1944beneficiaries)	Member Secretary

Instructions for Committee:

- Recommendation of a Minimum of 3 subject field experts (Neurology/Neurosurgery Specialist) shall be required for justification of the case.
- The committee shall contain at least One Neurologist and One Neurosurgeon.
- All rejections to be recorded carefully with well justified reasons.
- The technical committee shall consider cases in respect of beneficiaries under CGHS/ CS(MA) Rules, 1944.

5. Submission of Application:

The beneficiaries under CGHS/CS(MA) Rules, 1944 will submit a request for permission for DBS or other neuro implants to the Standing Technical Committee through their respective department in case of serving employees and the Additional Director, CGHS of the concerned zone or city, in case of pensioner CGHS Beneficiary.

6. Reimbursement Criteria

The DBS and other neuro implants are planned surgery and therefore, prior permission has to be obtained before the surgery is undertaken. The financial approving authority shall be as per extant rules of Delegation of Financial Powers.

7. Ceiling Rate

Device Type	Revised Cost (INR) inclusive of GST
DBS-Non-Rechargeable Device with Non-Directional Leads (Battery Life 5-8 years)	₹ 8,37,497
DBS-Non-Rechargeable Device with Directional Leads (Battery Life 5-8 years)	₹ 10,32,586
DBS-Rechargeable Device with Non-Directional Leads (Minimum Battery Life 15 years)	₹ 11,24,049
DBS-Rechargeable Device with Directional Leads (Minimum Battery Life 15 years)	₹ 13,89,969
New Battery (Implantable Pulse Generator) (Battery Life 5-8 years)	₹ 5,49,450
Intra-thecal Pump (Minimum Battery Life 7 years)	₹ 5,29,898
Spinal Cord Stimulator (Minimum Battery Life 10 years)	₹ 13,90,243

*The above-mentioned ceiling rate does not include the cost of surgery.

8. Guidelines/Indication:

Same as the conditions given under the section of 'Intended use' (Annexure-I, II and III) contained in the licence granted (Form MD-15) by the Central Drugs Standard Control Organization, under Rule 36 of Medical Devices Rules 2017.

9. Warranty:

The company shall offer a limited warranty for one year from the date of implantation, providing free replacement in the case of battery failure or device malfunction, as reported by the concerned physician.

10. Validity of rates:

The revised rates shall remain in force for a period of two years from the date of issuance of this Office Memorandum. This issue is with the approval of competent authority and concurrence of the IFD vide C.D No. 1467 dated 16.08.2024. ❐

F.No.3 1011/ 15/2022-Estt-A-1V Government of India Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions Department of Personnel & Training (Personnel Policy A-IV), New Delhi the 17th September, 2024

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Central Civil Services (Leave Travel Concession) Rules, 1988 - Relaxation to travel by air to visit North East Region, Jammu & Kashmir, Ladakh and Andaman & Nicobar - extension beyond 25.09.2024 -regarding.

The undersigned is directed to refer to this Department's OM No. 31011/15/2022-Estt.A-IV dated 11.10.2022 regarding relaxation to travel by air to visit North East Region, Jammu & Kashmir, Ladakh and Andaman & Nicobar, and to say that in relaxation to CCS (LTC) Rules, 1988, the scheme allowing Government servants to travel by air to North East Region (NER), Union Territory of Jammu and Kashmir (J&K), Union Territory of Ladakh and Union Territory of Andaman & Nicobar Islands (A&N) is extended for a further period of two years, w.e.f. 26th September, 2024 till 25th September, 2026.

2. The above Special Dispensation Concession is subject to the following terms & conditions: -

i. All eligible Government servants may avail LTC to visit any place in NER/A&N/J&K/Ladakh against the conversion of their one Home Town LTC in a four years' block period.

ii. Government servants, whose Home Town and Headquarters/place of posting are same, they are not allowed the conversion of any Home Town LTC as they are not eligible for the Home Town LTC facility.

iii. The Government servant whose Home Town is situated in NER/A&N/J&K/Ladakh will also be allowed conversion of Home Town LTC for availing this Scheme to visit any place in any one of the three regions out of the above mentioned four regions except the region where in his/her Hometown is situated.

iv. Fresh Recruits are also allowed conversion of one of the three Home Town LTCs in a block of four years, applicable to them to visit NER/A&N/J&K/Ladakh. In addition, they are allowed one additional conversion of Home Town LTC to visit UT of J&K/UT of Ladakh in a block of four years.

v. Government servants entitled to travel by air may avail this concession from their Headquarters in their entitled class of air by any airlines subject to the terms and conditions as enumerated in DoPT's OM. No. 31011/12/2022-Estt.A-IV dated 29.08.2022 read with DoPT's OM No. 31011/11/2023 - Pers. Policy A-IV dated 20.10.2023 (copies enclosed).

vi. Government servants not entitled to travel by air are allowed to travel by air in Economy class by any airlines subject to the terms and conditions as enumerated in DoPT's OM dated 29.08.2022 read with DoPT's OM No. 31011/11/2023 - Pers. Policy A-IV dated 20.10.2023 in the following sectors:-

a. Between Kolkata/Guwahati and any place in NER.

b. Between Kolkata/ Chennai/Visakhapatnam and Port Blair.

c. Between Delhi/Amritsar and any place in J&K/Ladakh.

Journey for these non-entitled employees from their Headquarters upto Kolkata/ Guwahati/ Chennai/ Visakhapatnam / Delhi/Amritsar shall be undertaken as per their entitlement.

vii. Air travel by Government employees to NER, J&K, Ladakh and A&N as mentioned in para (v) and (vi) above is allowed whether they avail the concession against Anywhere in India LTC or in lieu of the Home Town LTC, as permitted.

viii. Government servants not entitled to travel by air are also allowed to travel by air in Economy class by any airlines to any place in

NER/A&N/J&K/Ladakh from their Headquarters directly, however, the reimbursement will be subject to the conditions as enumerated in DoPT's OM No. 31011/ 12/2022-Estt.A-IV dated 29.08.2022.

ix. The instructions regarding booking of air tickets through authorized travel agents, best available fares, slots, booking time, advances, reimbursement, etc., as mentioned in DoPT's OM No. 31011/12/2022- Estt.A-IV dated 29.08.2022 read with DoPT's OM No. 31011/11/2023 - Pers. Policy A-IV dated 20.10.2023 will also be applicable for this Special Dispensation Scheme.

3. All the Ministries/Departments are advised to bring it to the notice of all their employees that any misuse of LTC will be viewed seriously and the employees will be liable for appropriate action under the rules. In order to keep a check on any kind of misuse of LTC, Ministries/Departments are advised to randomly get some of the air tickets submitted by the officials verified from the airlines concerned with regard to the actual cost of air travel vis-a-vis the cost indicated on the air tickets submitted by the officials.

4. In their application to the persons belonging to Indian Audit and Accounts Department, these orders are issued as mandated under Article 148(5) of the Constitution and after consultation with the Comptroller & Auditor General of India. —

5. Hindi version will follow. ❐

F. No. 31011/12/2022-Estt.A-W Government of India Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions Department of Personnel & Training Establishment A-W Desk, New Delhi the 29th August, 2024

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Instructions on booking of Air Tickets on Government Account In respect of Leave Travel Concession (LTC) - regarding.

The undersigned is directed to refer to the above mentioned subject and to state that in view of the disinvestment of Air India and the consolidated instructions issued consequently by Department of Expenditure vide O.M. No. 19024/03/2021- E.IV dated 16.06.2022, which is also applicable in case of air journey in respect of LTC, it has been decided that:

i. In all cases of air travel in respect of LTC, air tickets shall be purchased only from the three Authorized Travel Agents (ATAs), namely:

(a) M/s Balmer Lawrie & Company Limited (BLCL),

(b) M/s Ashok Travels & Tours (ATT),

(c) Indian Railways Catering and Tourism Corporation Ltd. (IRCTC).

ii. The choice of the travel agent for booking of ticket from the three authorized travel agents is left open to the Ministry/Department and the official in case of self booking, based on convenience and service quality. No agency charges/convenience fees will be paid to these ATAs.

iii. Government employees are to choose flight having the Best Available Fare on their entitled travel class which is the Cheapest Fare available, preferably for Non-stop flight in a given slot, mentioned below, at the time of booking. They are to retain the print-out of the concerned webpage of the ATAs having flight and fare details for the purpose of the settlement of the LTC claims.

(a) On the day of travel in the desired 3 hours' slot of following time band -

00:00 hours to 03:00 hours, 03:00 hours to 06:00 hours, 06:00 hours to

09:00 hours, 09:00 hours to 12:00 hours, 12:00 hours to 15:00 hours,

15:00 hours to 18:00 hours, 18:00 hours to 2 1:00 hours, 2 1:00 hours to 24:00 hours.

(b) With provision of optimizing within a 10% price band, for convenience and comfort.

iv, Employees are encouraged to book flight tickets at least 21 days prior to the intended date of travel on LTC, to avail the most competitive fares and minimize burden on the exchequer.

v. Employees are also encouraged to avoid unnecessary cancellations. Cancellations made less than 24 hours before intended travel on I4TC, will require the submission of a self-declared justification by the employee. All the three ATAs have been directed to provide zero/nil cancellation charges. Till then, cancellation charges are to be reimbursed for all cases where cancellation was due to the circumstances/reasons beyond the control of Government employee.

vi. Employees should preferably book only one ticket for each leg of intended travel on LTC. Holding of more than one ticket is not allowed.

vii. While tickets may be arranged by the office through the travel agent, employees are encouraged to make ticket booking digitally through the

SelfBooking Tool/online booking website/portal of these 3 ATAs only. Employees must register their official Government Email-Id with these three agencies to book their air tickets digitally through above modes for travel by any airlines.

viii. In case of unavoidable circumstances, where the booking of ticket is done from unauthorized travel agent/website, the Financial Advisors of the Ministry/Department and Head of Department not below the rank of Joint Secretary in subordinate/attached offices are authorized to grant relaxation.

ix. No Mileage Points will be generated against travel on Government account.

Provisions for Advances

(i) Government employees entitled for air travel, may apply for LTC advance with the print-out of the concerned webpage of authorized travel agency having suitable flight and fare details while tracking the fare of the flight under the three hour time slot, as mentioned at Para I(iii)(a) above, at least 30 days 'prior to the intended date of journey.

(ii) Government employees not entitled for air travel and wish to travel by air but not under the Special Dispensation Scheme, may apply for LTC advance with reference to Rail/Bus fare.

(iii) Those Government employees who axe not entitled for air travel but who wish to travel by air under the Special Dispensation Scheme, may apply for LTC advance with reference to Rail/Bus fare from their Headquarters/place of posting up to Kolkata/ Guwahati/ Chennai/ Visakhapatnam/ Delhi/Amritsar plus air fare (indicated in print-out of the concerned webpage of authorized travel agency having suitable flight and fare details) from the relevant railhead in Kolkata/ Guwahati/ Chennai/ Visakhapatnam/ Delhi! Amritsar till the place of visit in North East Region/Union Territory of Jammu & Kashmir/Union Territory of Andaman & Nicobar/Union Territory of Ladakh.

Provisions for Reimbursements

(i) In case, at the time of actual booking of the ticket after receiving the advance, there is any difference in fare owing to the time gap between request for advance and grant of advance, the difference in fare will be adjusted at the time of settlement of LTC claim.

(ii) In all cases wherein the non-entitled Government employees travel by air under Special Dispensation Scheme directly from their Headquarters/place of posting to the place of visit in NER/J&K/A&N/Ladakh, the Government employees must take the print-out of the concerned webpage having flight and fare details of the flight for relevant railhead viz. Kolkata/ Guwahati/ Delhi! Amritsar/ Chennai/ Vishakhapatnam to the place of visit viz. NER or UT of J&K or UT of Ladakh or UT of A&N within the same time-slot where the direct flight has been booked for the purpose of reimbursement. In case the flight tickets are not available in the same slot, the print out of the details of the flights available in the next slot may be retained.

In such cases, the reimbursement will be restricted to the actual air fare for the direct journey or the fare entitled under Special Dispensation Scheme, whichever is less.

(iii) Government employees not entitled for air travel and wish to travel by air but not under the Special Dispensation Scheme, are also required to book their air ticket through only the three ATAs mentioned above irrespective of booking time limit. However, the reimbursement will be restricted to the actual air fare or the entitled train/bus fare for the shortest route, whichever is less. ❐

F. No. 31011/11/2023 - Pers. Policy A-IV Government of India Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions Department of Personnel & Training Pers. Policy A-IV Desk, New Delhi the 20th October, 2024

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Modifications in instructions on booking of Air Tickets on Government Account in respect of Leave Travel Concession (LTC) — reg.

The undersigned is directed to refer to this Department's OM No. 31011/12/2022-Estt.A-IV dated 29.08.2022 regarding instructions on booking of Air Tickets in respect of Leave Travel Concession (LTC). The Department of Personnel and Training (DoPT) has been receiving a number of representations seeking clarifications on issues relating to the settlement of claims, particularly of those government employees who have not retained the screenshot of the concerned webpage of the authorised travel Agents (ATAs) during the booking of air tickets, as provided under the OM dated 29.8.2022 referred to above.

2. In view of the above, the matter has been examined and with the approval of competent authority, the following changes/modifications in the prescribed procedure are made for the convenience of

Government employees: -

(i) All three authorized travel agents, viz. M/s Balmer Lawrie & Company Limited (BLCL), M/s Ashok Travels & Tours (AIT), and Indian Railways Catering and Tourism Corporation Ltd. (IRCTC) are to display the details of the flight having the cheapest fare and the flight(s) having the fare 10% more than the cheapest fare only, in the desired time slot, at the time of booking the air tickets by the Government employees for the purpose of LTC journey. Therefore, the booking of air ticket for the purpose of LTC on the website of these three authorized travel agents shall itself be a proof that the ticket booked by the individual government employee was of the cheapest fare as provided under the guidelines.

(ii) All three authorized agents shall indicate the word 'LTC' on tickets issued for the LTC journey; and

(iii) In all cases wherein the non-entitled Government employees are to travel by air under Special Dispensation Scheme directly from their Headquarters/place of posting to the place of visit in NER/J&K/A&N/Ladakh, the Government employees shall continue to take the print-out of the concerned webpage having flight and fare details of the flight for relevant railhead viz. Kolkata / Guwahati / Delhi/Amritsar/ Chennai/ Vishakhapatnam to the place of visit viz. NER or UT of J&K or UT of Ladakh or UT of A&N within the same time-slot where the direct flight has been booked for the purpose of reimbursement. In case the flight tickets are not available in the same slot, the print out of the details of the flights available in the next slot may be retained for the purpose of settlement of claims, as provided under Point (ii) of the title

"Provisions for Reimbursement" in OM dated 29.8.2022, referred to above.

3. Further, all the three ATAs have also been directed to allow the registration of those employees who do not have official email accounts provided their administrative office sends their details depicting their names, employee code no., private email IDs and mobile numbers, etc. to the travel agents for the purpose of booking the air tickets in respect of LTC journey.

4. For the sake of convenience, the links of the three authorized travel agents are as below:

(i) 'M/s Balmer Lawrie & Company Limited', BLCL (https://govemp.balmerlawrietravelapp.com), (ii) 'M/s Ashok Travels & Tours', ATT' (httpsi/www.attitdc.in) and (iii) Indian Railways Catering and Tourism Corporation Ltd., 'I ROTC' (https ://www.air.irctc.co.in).

5. All the Ministries/Departments are once again advised to bring it to the notice of all their employees that any misuse of LTC shall be viewed seriously and appropriate action as deemed fit under the relevant rules will be taken against the defaulting employees. In order to keep a check on any kind of misuse of LTC, Ministries/Departments are advised to randomly get some of the air tickets submitted by the officials verified by the airlines concerned with regard to the actual cost of air travel vis-a-vis the cost indicated on the air. tickets submitted by the officials.

6. Hindi version will follow. ❐

No.6/8/2023-Pers.Policy (Deputation/Re-employment) Pt. XV(i) Government of India Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions Department of Personnel & Training, New Delhi the 24th September, 2024

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Deputation of Group 'C'. employees of the Central Government to the State Governments/ Union Territories Admn.- Modification in guidelines - regarding.

The undersigned is directed to invite attention to the consolidated guidelines/instructions dated 28.03.2024 uploaded on the website of the Deptt. of Personnel & Training (DoPT) regulating the terms and conditions governing deputation/foreign service of employees to/from Central government including instructions/guidelines to be followed in connection with transfer on deputation / foreign service of Central Government employees_ to ex-cadre posts under Central Government /State government /Union Territories administration/Public Sector Undertakings /Autonomous Bodies/ Statutory Bodies/ Universities./ Local Bodies etc. and vice versa.

2. In consonance with the provisions governing deputation of Group 'A' officers of the Central Government to ex-cadre posts under State Government/ UT Admn., issued vide this Department's O.M. No.6/8/2023-Pers. Policy (Deputation/Re-employment) Pt. XV dated 15.03.2024 and suitably incorporated in the consolidated guidelines/instructions dated 28.03.2024 referred above, instructions have been issued vide this Department's OM of even number dated 30.08.2024 regulating deputation of Group 'B'

employees 9f the Central Government to the ex-cadre posts under a State Governme'nt /UT Administratio'n including PSUs/ Autonomous bodies/ Statutory Bodies/Universities/ Local Bodies under the State Governments/UT Administration .

3. Further to the instructions referred above, it has been decided that the deputation of the employees belonging to Group 'C' Cadres/Posts in the Ministries/Departments/Organisations under the Central Government to the State Governments/UTs Admn. including PSUs/ Autonomous bodies/Statutory Bodies/ Universities/Local Bodies under the State Governments/UTs Admn. shall be regulated by the following instructions/guidelines:

(i) All such cases shall be submitted for consideration and approval of the Competent Authority in the Ministry/Department/Organisation concerned;

(ii) Such deputation will be available to the employees only after completion of nine years of service in parent Cadre.

(iii) However, the employee, after completion of 7 year of service in the Ministry/Department/Organisation, may proceed on deputation to any State of North. Eastern Region, UTs of Jammµ and Kashmir, Andaman and Nicobar, and Lakshadweep or on foreign service to any entity controlled by and located in these States/UT's.

(iv) The employees may also go on deputation to any entity controlled by and located in States/UTs on spouse grounds after completion of 6 years in the Cadre.

(v) A request for such deputation will only be entertained by the Cadre Controlling Authority or the administrative Ministry/Department/Organisation concerned if it is received along with NOC/consent of. the borrowing State Government/UT Admn.

(vi) All such cases of deputation to State Governments/UT Admin. will be initially restricted to three years, extendable by two more years after review. Where the initial period of deputation is for less than three years, continuation of the officer on deputation basis beyond the initial period, shall be treated as a case of extension of that deputation, requiring prior approval of the Competent Authority.

(vii) The total allowable period of such deputation to any State Government/UT Administration including PSUs/ Autonomous bodies/Statutory Bodies/ Universities/Local Bodies in the States/UT Administration in the entire career of the officer shall be restricted to five years. No extension of deputation beyond five years shall be allowed.

(viii) Employees who are already on deputation may be allowed to complete their full term.

(ix) A request for extension of deputation beyond the initially approved period of deputation (subject to restriction of the overall tenure of deputation of five years) will be entertained by the Cadre Controlling Authority or the administrative Ministry/Department/ Organisation concerned, as the case may be, only if it is forwarded along with NOC of the borrowing State Government/ UT Admn, with cogent reasons and at least three months prior to the expiry of the period of deputation. In case no specific approval of the Central Government for extension is received within the period for which deputation was originally valid, the employee shall have to be relieved positively and immediately on completion of the original tenure.

(x) In cases where an employee has completed the approved period of deputation, it would be made clear to the employee concerned and to the Cadre Controlling Authority or the administrative authority concerned that adverse notice will be taken at the time of empanelment and promotion of the employee if he/she continued on such deputation beyond the approved period of deputation.

(xi) Deputation is valid only for the period for which it is allowed by the Central Government and any extension is neither automatic nor should be presumed merely on the ground that the Cadre Controlling Authority/ administrative authority or the employee or both made a request for extension. As such, the employee concerned shall be entitled to draw salary etc. in the borrowing State Government/UT Admn to which he/she has been deputed only for the period for which he/she has been allowed deputation by the Government of India: The employee shall not be entitled to draw salary etc. after expiry of the period of deputation. An employee on such deputation shall relinquish charge and get himself/herself relieved on the last day of his/her deputation, if no orders extending his/her deputation by the concerned Cadre Controlling Authority or the administrative authority concerned, as the case may be, are received in the borrowing State Government/UT Admn.

(xii) An employee who does not handover charge at the end of the approved period of deputation will be immediately liable to disciplinary action and break-in-service for the period beyond the approved date. All orders of deputation will carry endorsement to this effect. Further, an endorsement will also be made to the Pay & Accounts Office concerned to stop payment of salary to the employee beyond the approved period of deputation.

(xiii) Copies of all deputation orders must be marked to/served on the employee concerned along with State Government/UT/ borrowing Organisation and others concerned.

(xiv) In the event the employee overstays for any reason whatsoever, he/she is liable for disciplinary action and other adverse Civil/Service consequences which would include the period of overstay not being counted towards service for the purpose of pension and any increment due during the period of overstay being deferred with cumulative effect, till that date on which he/she re-joins in the parent Cadre.

(xv) The State Governments/UT Admn,/borrowing Organisations are advised to relieve the employee promptly on the last date of completion of the deputation tenure without fail unless the competent authority in the Central Government extends the period of deputation in writing prior to its date of expiry.

(xvi) **Grant of leave to the employee on completion of tenure of deputation:** On reversion from such deputation, the employee concerned might be allowed leave not exceeding two months by the concerned borrowing State Government/UT Admn. where the employee was on deputation. The employee concerned should apply for further leave to his/her parent Cadre. Further, such leave is debitable from the leave account of the employee concerned. .

(xvii) **Cooling off period:** 'Cooling off' requirement between two spells of deputation shall be governed by the relevant provisions: contained in 'Consolidated guidelines on deputation/foreign service for Central Government employees issued vide DOPT's O.M. No.DOPT-1716267915093 dated 28.03.2024.

(xviii) **Relaxation of policy guidelines:**

a. Cases where relaxation of any of the provisions of these guidelines is required will be put up to a designated Committee for a decision as to whether the proposal may be recommended to the Competent Authority for consideration, in relaxation of the existing guidelines,

b. **Composition of the Committee:** The composition of the Committee, constituted to consider such cases of Group 'C' employees of the Central Government, where relaxation of any of the provisions of the policy/guidelines is sought, may be decided by the Cadre Controlling Authority or the administrative Ministry/Department/ Organisation concerned, as the case may be.

c The designated Committee shall consider all such cases of deputation and give its recommendation on the relaxation sought. Cadre Controlling Authority or the administrative Ministry / Department / Organisation, as the case may be, may consider all cases of deputation of Group 'C' employees of Central Government to State Govts. / UTs Admn. involving relaxation of any of these provisions and take an appropriate decision;

d. The designated Committee shall also review all the cases of deputation involving employees belonging Group 'C'. posts/C;irades to the State Govts. / UT Admns, where the remaining tenure of the employee on deputation is six months or more, and give its recommendation on his / her continuance till completion of the approved deputation term. The cases recommended by the Committee shall be submitted for consideration and approval of the Competent Authority.

(xix) In terms of clause (v) pf this O.M., the designated Committee shall consider all cases seeking extension of deputation term beyond 3 years. Only those cases recommended by the Committee for extension of deputation beyond 3 years, would be placed before the Competent Authority for consideration. As a one time measure, the aforesaid Committee shall also review present cases of deputation to State Governments/UT Administration PSUs/ Autonomous bodies/ Statutory Bodies/ Universities/Local Bodies under the States/UT Administration where the remaining tenure cif the officer is six months or more. After review, the Committee shall give its recommendation for continuation of the employee concerned till the end of the term of deputation. Such cases shall thereafter also be submitted for consideration and approval of the Competent Authority.

4. All other instructions /guidelines consolidated vide DoPT's OM and 28.03.2024 shall remain unaltered.

5. These guidelines shall be_ applicable with immediate effect.

6. Hindi version will follow.

❐

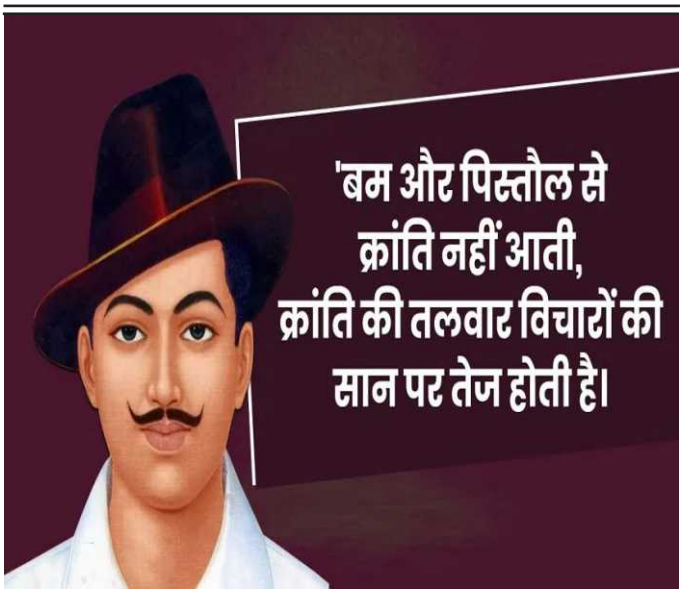

NAVALSHIP REPAIR YARD KARWAR BPMS WON 3/6
IN WORKS COMMITTEE & 3/6 IN CANTEEN COMMITTEE

17 FAD BADOWAL LUDHIYANA DEPOT BPMS WON 5/5
IN WORKS COMMITTEE

VARIOUS MEMBERS OF NAVAL DOCKYARD HAS JOIN
MEMBERSHIP OF INCMS UNION BPMS / BMS

RNI No. MAHBIL/2002/8760 Publication Date : 31 September. 2024 MONTHLY NEWS PAPER
Postal Regd. No. Misc-II/C.P.M//007/K.PH.O./2020 dt 29-12-2020 (for 2021-23)• Posted on Dt. 26,27th Monthly

SPECIAL BULLETIN

Date:-16|Sep|2024 Sr.No- 11/2024

Congratulations

On 28/Aug/2024 , In the works committee election held at ADRDE AGRA, BPMS affiliated union won the majority by 04/05 seats.

On 10/Sep/2024 , In the works committee election held at MES , Meerut , BPMS affiliated union won the majority by 04/05 seats.

Hearty congratulations to the entire team.

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएँ हमें इस पते पर भेजिये।

If undelivered please return to :

"Pratiraksha Bharti"
C/o. Bharatiya Pratiraksha Mazdoor Sangh
2, Naveen Market, Kanpur - 208 001
Mob. : 9450153677, Tel./Fax : 0512-2332222
Website : www.bpms.org.in
E-mail : gensecbpms@yahoo.co.in, cecbpms@yahoo.in

बुक पोस्ट

Publisher and Owner : Bhartiya Pratiraksha Mazdoor Sangh, 2 Naveen Market, Kanpur-208001
Printed at Chhaya Press 8/208, Arya Nagar, Kanpur-208002 ● Mob. : 9839223650